भर्ती विधान

मेरा JOB मुझे मिलेगा

युवा घोषणा पत्र

हम वचन निभाएंगे

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी

विषय सूची

	पृष्ठ क्रमांक
भूमिका	3
भर्ती क्रांति नौकरियों और रोजगार के अवसर प्रदान करना	4
भरोसा भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का भरोसा बहाल करना	9
भविष्य निर्माण युवाओं के बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करना	11
भागीदारी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाना	13
भलाई शारीरिक और मानसिक खुशहाली को बढ़ावा देना	15

भूमिका

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की सात करोड़ युवा आबादी को उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रचनात्मकता और क्षमता से भरपूर ये युवक-युवतियां ही हमारे देश का भविष्य हैं।

कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पिछले एक वर्ष के दौरान पूरे प्रदेश के युवाओं से बातचीत और परामर्श करके उनकी परेशानियों, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को समझने की कोशिश की है। यह घोषणापत्र विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों, पेशेवर युवाओं, अपने भविष्य निर्माण के लिए परेशान शिक्षित और बेरोजगार नौजवानों और हाशिए के समूहों से जुड़े युवाओं की आकांक्षाओं का दस्तावेज है, जिनमें अपार क्षमता तो है, लेकिन अपने इन सपनों को साकार करने के लिए उनके पास अवसर नहीं हैं। इस घोषणापत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है कि कैसे हम पूरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उद्यमों के अवसर प्रदान करेंगे।

कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि प्रगति की बुनियाद शिक्षा में है, इसलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और शिक्षा में व्यवस्थागत असमानताओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करेगी। इससे उद्यमिता और रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए राज्य की क्षमता उल्लेखनीय ढंग से बढ़ेगी। विनिर्माण समूहों के विकास, रचनात्मक उद्योगों का विस्तार, तकनीकी नवाचार के लिए विशेष प्रयास, स्थानीय व पारंपरिक हस्तशिल्प एवं छोटे व्यवसायों के लिए विशेष मदद प्रदान करने के नये रास्ते बनाए जाएंगे।

युवाओं की शक्ति, उनकी आजादी, आत्म-अभिव्यक्ति, जुनून, उत्साह, ऊर्जा, रचनात्मकता और दृढ़-संकल्प किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रेरक शक्ति का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा वातावरण तैयार करने की प्रतिज्ञा लेती है जो इन गुणों को फलने-फूलने में सक्षम बनाए, ताकि उत्तर प्रदेश के लाखों युवा आशा और उम्मीद से भर जाएँ और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए अपने सपने पूरे कर सकें।

भर्ती क्रांति

नौकरियों और रोजगार के अवसर प्रदान करना

उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं जो रोजगार के लिए योग्य हैं, लेकिन यहां रोजगार के अवसरों की कमी है। पिछले पांच सालों में बेरोजगारी पांच गुना तक बढ़ गई है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए यह तीन गुना और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए चार गुना तक बढ़ गई है। स्नातकों के लिए बेरोजगारी 21% से बढ़कर 51% हो गई है। तकनीकी डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी 13% से बढ़कर 66% और तकनीकी स्नातकों में 19% से बढ़कर 46% हो गई है। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक सार्थक भविष्य प्रदान कर पाने में पूरी तरह विफल रही।

सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में नौकरियां उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में रोजगार के नये अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। युवा अपना बेहतर भविष्य बनाने की उम्मीद में ऐसी स्थायी और अच्छे मानदेय वाली नौकरियों में भर्ती होना चाहते हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण पहलू के प्रति वर्तमान सरकार की भयावह लापरवाही, सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने की नीति, भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति ने लाखों युवाओं की आशाओं को लगातार कुचला है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस व्यवस्था से विश्वास ही उठ गया है जिसपर उनके भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी है।

उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं का भरोसा बहाल करने और भविष्य निर्माण के लिए उन्हें सशक्त करने के क्रम में कांग्रेस प्रतिज्ञा लेती है कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें से 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे।

यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेंस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ख़ाली पड़े 1.5 लाख पदों को भरा जाएगा।
- बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त प्रधानाचार्य के 1 लाख पदों को भरा जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के 38,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा।
- उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त 2,500 पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त 400 पद, बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त 9,000 पद, तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त 5,800 पद और व्यावसायिक शिक्षा विभाग में रिक्त 7,400 पद भरे जाएंगे।
- शारीरिक शिक्षा विभाग में रिक्त 32,000 प्रशिक्षकों के पद और संस्कृत विद्यालयों में रिक्त 2,000 पदों को भरा जाएगा।
- सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त 6,000 पदों को भरा जाएगा। इनमें जिला अस्पतालों में 600 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में 800 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में विशेषज्ञ डॉक्टरों (बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ और सर्जन) के 2,000 रिक्त पद शामिल हैं। इसके माध्यम से प्रति सरकारी डॉक्टर 20,000 मरीजों की वर्तमान दर को घटाकर 13,333 मरीज प्रति डॉक्टर किया जाएगा। वर्तमान में यह दर राष्ट्रीय औसत के 10,000 मरीज प्रति डॉक्टर की दोगुनी है।
- डॉक्टरों को सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में आवास और परिवहन सुविधाएं, प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि, दुर्गम क्षेत्रों के लिए भत्ता सहित उचित पैकेज और लाभ की व्यवस्था की जाएगी।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उक्त प्रस्तावों को मिड-लेवल सर्विस प्रोवाइडर की अवधारणा के साथ संयोजित किया जाएगा। क्लिनिकल और पैरामेडिकल पृष्ठभूमि वाले स्नातकों के लिए योग्यता बढ़ाने वाले ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे ताकि वे उप-केंद्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता हासिल कर सकें।
- जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त 1,900 पद, सरकारी अस्पतालों में नर्सों के रिक्त 1,500 पद, पीएचसी और उप-स्वास्थ्य केंद्रों में सहायक नर्स मिडवाइफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सहायकों के 29,100 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएँगी।
- सीएचसी में रेडियोग्राफर के 500 और लैब टेक्नीशियन के 1,800 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 19,300 रिक्त पद तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 27,100 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- आशा बहू के 4,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- आयुष विभाग में 8,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

- उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रिक्त 1.15 लाख पदों को भरा जाएगा। इनमें 19,900 एसआई, 38,300 कांस्टेबल और 51,400 कांस्टेबल के पद भी शामिल होंगे।
- राज्य सचिवालय में रिक्त 3,000 पद, लोक निर्माण विभाग में रिक्त 11,000 पद, महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त 6,000 पद, पंचायती राज विभाग में रिक्त 9,000 पद, राजस्व विभाग में रिक्त 29,000 पद, कृषि विभाग में रिक्त 12,000 पद, खाद्य एवं रसद विभाग में रिक्त 4,500 पद, सिंचाई विभाग में रिक्त 20,600 पद, वन विभाग में रिक्त 4,700 पद, वित्त विभाग में रिक्त 4,500 पद, टैक्स रजिस्ट्री विभाग में रिक्त 9,000 पदों समेत राज्य सरकार के शेष सभी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बंद की जाएगी और संविदा रोजगार को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

- 'उद्योग सहायक' नाम से शिक्षित पुरुषों और महिलाओं का एक नेटवर्क बनाया जाए, जो सूक्ष्म-उद्यमियों को मदद करेगा और मामूली शुल्क लेकर उन्हें सरकारी लाभों, जैसे ऋण और सब्सिडी के साथ-साथ डिजिटल भुगतान और कर अनुपालन जैसी सेवाओं से जोड़ेगा। सरकार एक लाख तक उद्योग सहायकों को ट्रेनिंग और उपकरण मुहैया कराएगी। इन उद्योग सहायकों को बड़ी संख्या में औद्योगिक समूहों में तैनात किया जाएगा।
- जिले के भीतर विभिन्न समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए 'वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट' नीति में ढील दी जाएगी। सभी उद्योग जिनके पास 100 से अधिक इकाइयां हैं, उन्हें एक समूह घोषित किया जाएगा। पारंपरिक समूहों को बढ़ावा देकर और नये समूहों के निर्माण के जरिये उत्तर प्रदेश के उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक समूह को कर्ज, मार्केटिंग, कौशल और प्रौद्योगिकी प्रदान की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सीवरेज का ढांचागत सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा।

नीचे दी गई तालिका में उन औद्योगिक समूहों को दर्शाया गया है जिन्हें ऊपर बताए गए तरीकों से विकसित किया जाएगा:

औद्योगिक समूह	
जिला	**उद्योग**
आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर	हथकरघा बुनाई
मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र	कालीन
फर्रुखाबाद, एटा, आगरा	आलू प्रॉसेसिंग
कुशीनगर, वाराणसी, गोरखपुर, श्रावस्ती	आध्यात्मिक पर्यटन
वाराणसी	एकीकृत पर्यटन और बुनाई
उन्नाव, कानपुर, आगरा	चमड़ा और जूते
फिरोजाबाद	कांच के सामान

बुलंदशहर	मिट्टी के बर्तन
बाराबंकी	पुदीना
फर्रुखाबाद, कन्नौज	प्रिंटिंग & परफ्यूम
सहारनपुर	लकड़ी पर नक्काशी
मुरादाबाद, अलीगढ़	पीतल और ताले
आगरा	एकीकृत पर्यटन और पत्थर
लखनऊ	बागवानी (मैंगो प्रॉसेसिंग)
***नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद में नए हब**	

- 30 वर्ष से कम उम्र के उद्यमियों को बिना गारंटी के 5 लाख तक का कर्ज प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिये जाने वाले गारंटी मुक्त ऋणों को ठीक से लागू किया जाएगा।
- स्टार्ट-अप के प्रचार और प्रोत्साहन के लिए 5,000 करोड़ रुपये का 'सीड स्टार्ट-अप फंड' स्थापित किया जाएगा। इसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रत्येक जिले में राज्य द्वारा चलाए जाने वाले 'यूथ मार्ट' स्थापित किये जाएंगे। ये यूथ मार्ट प्रत्येक जिले में हथकरघा, स्थानीय शिल्प, मिट्टी के बर्तन, ऊन का काम, बढ़ईगिरी, गुड़िया बनाने और विशेष कृषि उत्पादों से जुड़े उद्यमों की स्थापना और विकास के लिए योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन आदि के स्तर पर सहायता करेंगे।

  'यूथ मार्ट' की दुकानें स्वयं सहायता समूहों, सिविल सोसाइटी संगठनों और स्थानीय सहकारी समितियों से लाभकारी दरों पर थोक में सीधे खरीद करेंगी और इन उत्पादों की पैकेजिंग, विपणन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं तक पहुंच में सहायता करेंगी।

  - ये 'यूथ मार्ट' ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
  - प्रत्येक 'यूथ मार्ट' में एक विशेष सोशल मीडिया कौशल केंद्र होगा जो युवा उद्यमियों को सोशल मीडिया टूल्स का उपयोग करके अपने उत्पादों के विपणन और प्रचार के लिए मुफ्त सहायता प्रदान करेगा।
  - लुप्त हो रहे शिल्प और परंपराओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें दुनिया के सामने फिर से लाने के लिए उनके विकास पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक जिले के कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

- कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि हर मंडल में सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों में भर्ती के इच्छुक युवकों और युवतियों के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जाएं।
- पूरे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी संचालित उचित मूल्य की दुकानों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इन नेटवर्क को चलाने के लिए महिलाएं, वंचित तबकों के लोगों और विशेष क्षमता वाले लोगों जैसे कि विकलांग, अपराध और बीमारी के शिकार महिलाओं अथवा पुरुषों को रखा जाएगा। ये दुकानें रोजगार पैदा करने के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देंगी और कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे छोटे व्यवसायों द्वारा उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में सहायता प्रदान करेंगी। इनमें से 50% दुकानें 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम करोड़ों देशवासियों को रोजगार प्रदान करते हैं। इन उद्यमों को सरकार के प्रिय पूंजीपतियों को सौंपने से करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं खत्म हो रही हैं और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आरक्षण की गारंटी भी खत्म हो रही है। करोड़ों भारतीयों की मेहनत और खून-पसीने से इन सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण संभव हुआ है और सही मायने में इनपर उन्हीं का हक है।

कांग्रेस पार्टी लाभकारी सार्वजनिक उद्यमों के मनमाने निजीकरण को रोकने और भारत की जनता के लिए उनका स्वामित्व बहाल करने की प्रतिज्ञा लेती है।

भरोसा

भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का भरोसा बहाल करना

वर्तमान भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को नष्ट कर दिया गया है। परीक्षाओं पर माफिया का नियंत्रण है और धोखाधड़ी एक उद्योग बन गया है जिसके चलते युवा अभ्यर्थियों को बेहद पीड़ा झेलनी पड़ रही है। मेहनती और नौकरियों के असली हकदार अभ्यर्थी प्रवेश फॉर्म, ट्यूशन और तैयारी के लिए भारी-भरकम खर्च के अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनमें से कई को रोजगार की गारंटी के बिना वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। राज्य में सिर्फ पिछले 5 वर्षों में 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं, परीक्षा के बाद कट-ऑफ अंक बदल दिए गए हैं या फिर युवा अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करते हुए उन्हीं पदों के लिए फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया गया है।

युवाओं के प्रति होने वाले इस अंतहीन शोषण और अन्याय को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिज्ञा लेती है कि प्रदेश में एक ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बहाल की जाएगी जो परीक्षा प्रक्रियाओं को भ्रष्टाचार मुक्त, बाधा रहित और युवाओं के लिए सुगम बनाएगी।

- राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- प्रदेश के सभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त बसें और मुफ्त रेल यात्रा प्रदान की जाएगी, जहां प्रवेश पत्र को मुफ्त पास माना जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक अधिसूचना से लेकर नियुक्ति तक की थकाऊ और लंबी प्रक्रिया को सुधारा जाएगा और इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। हर भर्ती के लिए एक जॉब कैलेंडर तैयार किया जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिज़ल्ट की तारीख़ और नियुक्ति की तारीख दर्ज होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिसूचना जारी होने की तारीख और नियुक्ति की तारीख के बीच छह महीने से ज्यादा का फासला ना हो। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस कैलेंडर में निर्धारित मानदंडों (जैसे कट-ऑफ अंक, पात्रता आदि) में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद कोई बदलाव नहीं होगा।

- परीक्षा कैलेंडर का उल्लंघन होने की स्थिति में तत्काल गंभीर जुर्माना लगाया जाएगा। इस परीक्षा कैलेंडर का किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर जवाबदेही तय करने के लिए विशेष कानून होगा, जिसके तहत जिम्मेदार अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई होगी।
- भर्तियों से संबंधित कानून का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक 'विशेष भर्ती आयोग' (Special Recruitment Commission) का गठन किया जाएगा। यह विशेष भर्ती आयोग परीक्षा कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करेगा, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों को हल करेगा और वर्तमान में भर्तियों के जो मामले अदालतों में हैं, उनका निपटारा कराएगा। इससे भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया का हस्तक्षेप बंद होने के साथ भर्ती प्रक्रिया में घोटाले, पेपर लीक और जान-बूझकर देरी जैसे भ्रष्टाचार समाप्त होंगे।
- विशेष भर्ती आयोग भर्तियों से संबंधित उन सभी मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करेगा जो वर्तमान में अदालतों में लंबित हैं, जैसे- शारीरिक शिक्षा के 32,000 शिक्षकों के पद, शिक्षक भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुल 21,000 पद, उर्दू शिक्षकों के 4000 पद आदि।
- 2021 में टीईटी का प्रश्नपत्र लीक हुआ, जिसके कारण 22 लाख युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ। ऐसी घटनाओं और परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- परीक्षा प्रश्नपत्रों को निर्धारित एवं गोपनीय जगहों पर ही छापा जाएगा। यदि किसी भी तरह का पेपर लीक होता है तो जवाबदेही तय की जाएगी और ऊपर से नीचे तक दोषी लोगों को सजा कड़ी मिलेगी।
- सभी सरकारी रिक्तियों के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड सार्वजनिक किया जाएगा। इस डैशबोर्ड को नियमित रूप से समय-समय पर अपडेट किया जाएगा, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और युवा आवेदकों को उपयुक्त नौकरियों और भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी खोजने के लिए आवश्यक विवरण एक जगह पर उपलब्ध हो सकेगा।
- ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सख्ती से लागू करने हेतु प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया के लिए एक 'सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक' नामित किया जाएगा। अगर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन होता है, जैसा कि हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, तो ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
- मौजूदा परीक्षा केंद्रों की समीक्षा करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आवेदकों के लिए भौगोलिक रूप से सुलभ हों।

भविष्य निर्माण

युवाओं के बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करना

मौजूदा भाजपा सरकार ने शिक्षा पर बजट आवंटन लगातार कम किया है। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर औसत खर्च सभी राज्यों की तुलना में कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में 40% स्कूलों में बिजली नहीं है। पूरे राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है।

युवा लड़के-लड़कियां उत्तर प्रदेश की शान हैं। समकालीन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की दृष्टि से उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवा अपने स्वास्थ्य, अपनी उन्नति और अपनी शिक्षा के लिए आदर्श सुविधाओं के हकदार हैं।

रोजगार के सार्थक अवसर युवाओं तक पहुंच सकें, इसके लिए मजबूत शैक्षिक ढांचा मुहैया कराने की जरूरत है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

- शिक्षा पर खर्च 2021-22 के बजट में बेहद कम (13%) रहा है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम किया जाएगा।
- राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल के मैदान और मेस जैसी सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों को प्रौद्योगिकी लैब, वर्चुअल लर्निंग स्पेस और ई-लाइब्रेरी जैसी नवीनतम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- छात्रों को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों में एक एडवांस प्लेसमेंट सेल स्थापित की जाएगी जो जरूरी संस्थाओं से संबद्ध और सक्रिय हो।

- स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए के लिए नवीनतम सुविधाओं से लैस नए आईटीआई संस्थानों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आईटीआई संस्थानों की संख्या मौजूदा 3,302 से बढ़ाकर 5000 की जाएगी। नए पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाएंगे और प्रदेश में इनकी संख्या मौजूदा 109 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। मौजूदा तकनीकी कॉलेजों में सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा।
- सभी जिला स्तरीय कॉलेज अपग्रेडेड सुविधाओं जैसे प्रयोगशालाएं, मुफ्त वाई-फाई, खेल के मैदान, पुस्तकालय और छात्रावास से लैस होंगे।
- शैक्षणिक सत्रों के अनावश्यक विलंब से छात्रों को होने वाले तनाव को कम करने के लिए शैक्षणिक सत्रों का सख्ती से समयबद्ध समापन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कानूनी पेशे की प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करने वाले युवा वकीलों की सुविधा के लिए साधन और योग्यता के आधार पर वजीफा प्रदान करने के लिए तीन साल की सहायता योजना शुरू की जाएगी। इलाहाबाद एवं लखनऊ में न्यायालय परिसर से कुछ दूरी पर प्रवास गृह स्थापित किए जाएंगे। उन्हें उपयुक्त पुस्तकालय और अन्य सहायता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

भागीदारी

लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाना

एक लोकतांत्रिक देश में युवाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के हक़ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारे युवा, एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ गारंटीकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में छात्रसंघ चुनावों पर प्रतिबंध, विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के लिए छात्रों पर पाबंदियां, छात्रों के अकादमिक करियर को नष्ट करने और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने जैसे अलोकतांत्रिक कृत्य प्रमुखता से किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी युवाओं के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को पुन: जाहिर करती है। यह स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहेगी जब तक युवाओं के लिए समानता व न्याय वाला और समावेशी वातावरण सुनिश्चित नहीं किया जाता।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, खास तौर पर वंचित समुदायों से आने वाले युवाओं के लिए सामाजिक न्याय के उपायों को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है:

- दलित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमित रूप से प्रदान की जाएगी जो भाजपा शासन के दौरान पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं की गई है। यह छात्रवृत्ति सतत बजटीय आवंटन के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।
- आवेदन करने में आसानी के लिए सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। सभी छात्रवृत्तियों को सीधे हस्तांतरण के लिए बैंक खातों से जोड़ा जाएगा। आवेदनों की डिजिटल प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल संख्या और दी गई राशि पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- छात्रवृत्ति का दायरा, दी जा रही राशि और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर योग्य छात्रों की सहायता हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक सहायता निधि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- दलित, ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को खुदरा दुकानें चलाने के लिए पांच लाख रुपये की पूंजी प्रदान की जाएगी। इससे इन वर्गों को सशक्त करने के साथ-साथ संबंधित समुदाय के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इन राशियों का 50 प्रतिशत 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
- यूपी के प्रत्येक जिले में दलित छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। मौजूदा दलित छात्रावासों के प्रति वर्तमान सरकार के द्वेषपूर्ण रवैये के तहत फंडिंग में कमी और जानबूझकर पर्याप्त सुविधाओं से वंचित रखने की नीति को ख़त्म किया जाएगा। मौजूदा दलित छात्रावासों को विभिन्न सुविधाओं के जरिये अपग्रेड किया जाएगा।
- सफाई कर्मचारियों के परिवार के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- कांग्रेस पार्टी मछुआरा, निषाद, राजभर, नोनिया, कुम्हार और मल्लाह जैसी अति पिछड़ी जातियों के युवाओं के लिए मत्स्य पालन, नौका व्यवसाय, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज व्यवसाय, सुरक्षा व्यवसाय, खेल उद्योग और संबंधित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित करेगी। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा जहां इन कौशलों की दरकार है।
- निषाद, राजभर, मल्लाह, नोनिया, कुम्हार और मछुआरा जैसे अति पिछड़े समुदायों के युवा जो किसी भी क्षेत्र में अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 1% ब्याज दर के साथ 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- बुनकर समुदाय के युवा जो अपना खुद का बुनाई या कोई अन्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 1% ब्याज दर के साथ 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- कांग्रेस पार्टी पुलिस बल में भर्ती के लिए समान अवसर प्रदान करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया के नियम ऐसे ना हों जो वंचित तबकों के युवाओं को मानक पूरा न कर पाने के चलते बाहर कर दें, जैसे न्यूनतम शारीरिक मानक।
- सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से छात्रसंघ के चुनाव होंगे।
- शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने और वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए झूठे आरोपों में फंसाए गए और जेल में डाले गए छात्रों से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
- ऐसे मामलों के कारण जिन छात्रों का शैक्षिक करियर बर्बाद हो गया है, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उन्होंने जिस स्तर पर पढ़ाई छोड़ी थी, उसी स्तर पर अपनी शिक्षा में फिर से प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी।

भलाई

शारीरिक और मानसिक खुशहाली को बढ़ावा देना

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना जरूरी है। रोजगार न होने के चलते अनिश्चितता और तनाव, कोविड-19 और शैक्षिक व व्यावसायिक अवसरों की कमी ने उत्तर प्रदेश की युवा आबादी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा है। यहां पुरुषों के 10-75 आयु वर्ग के लोगों के बीच शराब की खपत 45% है, जो राष्ट्रीय औसत 27% से बहुत ज्यादा है। प्रदेश में शराब की लत नियंत्रित करने के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है, ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 1.6 करोड़ है। प्रदेश के पुरुषों में भांग/गांजा का प्रचलन 3.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 1.2% का लगभग तीन गुना है। उत्तर प्रदेश में 28 लाख लोगों को भांग से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मदद की जरूरत है। प्रदेश में अफीम और हेरोइन जैसी नशीली दवाओं के शिकार तकरीबन 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें नशामुक्ति में मदद की जरूरत है। दर्द निवारक दवाओं, सांस के जरिये खींचने वाले केमिकल्स और नशा करने वाली दवाओं का दुरुपयोग भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है।

युवाओं के लिए कल्याणकारी, रचनात्मक और मनोरंजक उपायों की कमी इन समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाती है।

उत्तर प्रदेश के युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने वाला अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

- खेलों में स्थानीय कौशल जैसे सोनभद्र में तीरंदाजी, पश्चिमी यूपी में कुश्ती और बास्केटबॉल आदि को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। निषाद समुदाय में विशेष रुप से इन कौशलों के विकास के लिए प्रयागराज में एक ओलंपिक स्तर की नौकायन, गोताखोरी और तैराकी अकादमी की स्थापना की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश में क्रिकेट के व्यापक और समावेशी विकास के लिए विश्व स्तरीय अकादमी की स्थापना की

जाएगी। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष एक अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसमें चुने गए खिलाड़ियों को आईपीएल और अन्य प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट में जाने के लिए मदद दी जाएगी।

- उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के खेल प्रशिक्षकों के संवर्ग की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। जिलों में उनकी नियुक्ति को तर्कसंगत बनाया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन के साथ प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक ब्लॉक में प्रशिक्षित फिजियो-कोच के साथ सभी तरह के संसाधनों से युक्त एक जिम मुहैया कराया जाएगा।
- हास्य कलाकार, परफॉरमेंस आर्टिस्ट, गायक, संगीतकार, डांसर आदि बनने के इच्छुक युवाओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय मनोरंजन केंद्र/एम्फीथिएटर बनाए जाएंगे जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे।
- सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए वर्ष में एक बार एक भव्य उत्सव यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर संगीत, कॉमेडी, सिनेमा और फिल्म से जुड़ी प्रतिभाएं शामिल होंगी। यह आयोजन हर साल एक नये शहर में आयोजित किया जाएगा।
- न्यू मीडिया में नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी इन माध्यमों में रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रचनात्मक उद्योगों के साथ अनुबंध करेगी। लघु फिल्में, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स आदि को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और बढ़ती सोशल मीडिया प्रतिभाओं के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाके में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान अवसाद, व्यसन और नशीले पदार्थों के सेवन से उपजे मनोरोग, पुनर्वास और परामर्श सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। आधुनिक सुविधा से लैस यह संस्थान मरीजों को समग्र देखभाल प्रदान करने के लिए क्लिनिकल मनोविज्ञान, नर्सिंग, व्यावसायिक थेरेपी और मेडिकल सोशल वर्क से जुड़े विभागों की मदद से साक्ष्य-आधारित उपचार मुहैया कराएगा। इसमें संस्थान के अपने मरीजों के लिए वार्ड होंगे और बाहरी मरीजों के लिए विशेषज्ञ तैनात होंगे।

  यह संस्थान उत्तर प्रदेश और देश भर में सेवारत मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरों की अगली पीढ़ी के लिए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा। यह भारत और विदेशों में विशेषज्ञता वाले संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। यह राज्य के 4 क्षेत्रों- पूर्वांचल, पश्चिम, बुंदेलखंड और अवध के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा।
- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संघर्षों को दूर करने के तरीकों और चुनौतियों के बारे में संवेदनशीलता बढ़ाने, उपचार व मदद और सही जानकारी के देने के लिए हर महीने जागरुकता और परामर्श शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रदेश में युवाओं की जनसंख्या के अनुसार किशोरों के लिए कल्याण स्वास्थ्य क्लीनिकों (Adolescent Friendly Health Clinics-AFHC) की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन क्लीनिकों में सक्षम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी